INDIA'S NEW SPACE COMMUNICATION POLICY

India has made significant progress in the area of satellite communication in terms of realization of indigenous technology, facilities, systems and rollout of services in a systematic manner. The implementation space based communication services has been led by the Government with relevant contributions from Indian Industry to achieve self-reliance and bring in necessary capabilities within the country at par with global trends.

The satcom applications are growing in leaps and bounds with rapid advancements in the technology. The demand for satellite bandwidth is growing to meet the communication needs for socio-economic development, connecting inaccessible regions, national security and consumer services. In order to meet such demands and to capture due shares in global market, it is essential to augment the orbit-spectrum resources and develop new technologies in a sustained manner.

Space is becoming a vital frontier for strategic applications and India needs to augment its space capabilities to ensure its national security and sovereignty through appropriate monitoring and control measures/ mechanism under Government of India.

Taking cognizance of the above aspects and the Government's initiatives towards Self Reliant India (Aatmanirbhar Bharat), enhanced engagement of Indian industry and related stakeholders with a focus on "ease of doing business" and encouraging healthy competitiveness is vital to contribute to the growth of national economy.

Accordingly, the Spacecom Policy-2020 has been formulated, addressing various aspects of space based communication from any space object of nano, micro or large class of satellites operating in GSO & NGSO orbits including deep space, interplanetary, and inter-satellite communications.

भारत की नयी अंतरिक्ष संचार नीति

भारत ने स्वदेशी तकनीक, सुविधाओं, प्रणलियों और सेवाओं के प्रस्तुतिकरण को व्यवस्थित तरीके से साकार करने के मामले में सैटेलाइट संचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आत्मनिर्भरता हासिल करने और वैश्विक रूझानों के साथ देश के भीतर आवश्यक क्षमताओं को लाने के लिए भारतीय उद्योग जगत से प्रासंगिक योगदान के साथ सरकार द्वारा कार्यान्वयन अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाओं का नेतृत्व किया गया है।

तकनीकी में तेजी से प्रगति के साथ छलांग व सीमायें बढ़ती जा रही है। सामाजिक-आर्थिक विकास, दुर्गम क्षेत्रों, राष्ट्रीय सुरक्षा और उपभोक्ताओं को जोड़ने के लिए संचार जरूरतों को पूरा करने के लिए सैटेलाइट बैंडविड्थ की मांग बढ़ रही है। इस तरह की मांगों को पूरा करने के लिए और वैश्विक बाजार में उचित हिस्से पर कब्जा करने के लिए अर्बिट-स्पेक्ट्रम संसाधनों को बढ़ाने और निरंतर तरीके से नयी तकनीकी विकसित करना आवश्यक है।

अंतरिक्ष रणनीतिक प्रयोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सीमा बन रहा है और भारत को भारत सरकार के अधीन उपयुक्त निगरानी उपायों/तंत्र के माध्यम से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त पहलुओं और आत्म-निर्भर भारत (आत्म-निर्भर भारत) के प्रति सरकार की पहल को संज्ञान में लेते हुए, भारतीय उद्योग और संबंधित हितधारकों की 'व्यापार करने में आसानी' पर ध्यान केंद्रित करने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है।

इसके अनुसार ही 'स्पेसकॉम नीति-2020' तैयार किया गया है जो जीएसओ और एनजीएसओ कक्षाओं में संचालित होने वाले सैटेलाइट, नैनो, माइक्रो या बड़े वर्ग के किसी भी अंतरिक्ष वस्तु से अंतरिक्ष आधारित संचार के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करता है, जिसमें गहन अंतरिक्ष, इंटरप्लेनेटरी और इंटर सैटेलाइट संचार शामिल है।

SPACE POLICY

SPACECOM POLICY-2020:

The "Spacecom Policy-2020" aims at meeting the growing demands of space based communication requirements of the nation and advancements in the relevant technologies for self-sustenance in areas of commercial, secured and societal communications. The Policy fosters promotion of Indian industry as co-traveller along with Department of Space (DoS) towards meeting these objectives.

Under the ambit of Spacecom Policy-2020, the Government of India shall -

- adopt measures to monitor and authorize use of space assets for communication to or from Indian territory.
- ensure protection of space assets already put in place and adopt measures to bring in more space assets under the administrative control for enhancing ability to utilize space based communication for national needs.
- promote increased participation of commercial Indian industry to provide space based communications both within the country and outside.
- concentrate on realization of space based communication systems for addressing the requirements that cannot be effectively, affordably and reliably satisfied by commercial Indian industry either because of national security concerns or economic factors.
- provide a timely and responsive regulatory environment for the commercial Indian industry to establish and operate space based communication systems.

Department of Space being the administrative ministry in respect of space activities in India as per the allocation of Business Rules of Government of India, shall issue appropriate norms, guidelines and procedures including approval-mechanism from time to time for the services in the areas of secured communication, commercial and societal services under Spacecom-2020.

Accordingly, the Draft Space Based Communication Policy of India-2020 (Spacecom Policy- 2020) and draft Norms, Guidelines and Procedures for implementation of Spacecom Policy-2020 (Spacecom NGP-2020) are published for public consultation. ■

स्पेसकॉम नीति 2020

'स्पेसकॉम नीति-2020 का उद्देश्य राष्ट्र की अंतरिक्ष आधारित संचार आवश्यकताओं की बढ़ती मांगों और वाणिज्यिक, सुरक्षित और सामाजिक संचार के क्षेत्रों में आत्मनिर्वाह के लिए प्रासंगिक तकनीकी में प्रगति को पूरा करना है। नीति इन उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) के साथ सहयात्री के रूप में भारतीय उद्योग को बढ़ावा देती है।

स्पेसकॉम नीति-2020 के दायरे में भारत सरकार-

- भारतीय क्षेत्र से संचार के लिए अंतरिक्ष संपत्तियों के उपयोग की निगरानी और अधिकृत करने के लिए उपाय अपनाता है।
- राष्ट्रीय जरूरतों के लिए अंतरिक्ष आधारित संचार का उपयोग करने की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशासनिक नियंत्रण के तहत अधिक अंतरिक्ष संपत्ति को लाने के लिए और राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष आधारित संचार का उपयोग करने की क्षमता बढ़ाने के लिए।
- देश व बाहर दोनों जगह अंतरिक्ष आधारित संचार प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक भारतीय उद्योग की बढ़ी हुई भागीदारी को बढ़ावा देना।
- राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं या आर्थिक कारकों के कारण या तो वाणिज्यिक भारतीय उद्योग द्वारा प्रभावी, किफायती और मजबूती से संतुष्ट नहीं की जा सकने वाली आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अंतरिक्ष आधारित संचार प्रणालियों की प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करना।
- वाणिज्यिक भारतीय उद्योग को अंतरिक्ष आधारित संचार प्रणाली को स्थापित करने और संचालित करने के लिए एक समयबद्ध और उत्तरदायी नियामक वातावरण प्रदान करना।
- अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के व्यवसायिक नियमों के आवंटन के अनुसार भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालय है, जो स्पेसकॉम 2020 के तहत संचार, वाणिज्यिक व सामाजिक सेवाओं व सुरक्षित क्षेत्रों में सेवाओं के लिए समय-समय पर अनुमोदन तंत्र सहित उचित मानदंड, दिशानिर्देश और प्रक्रियाओं को जारी करेगा।

इसके अनुसार भारत की ड्राफ्ट अंतरिक्ष आधारित संचार नीति 2020 (स्पेसकॉम नीति-2020) और स्पेसकॉम नीति-2020 (स्पेसकॉम एनजीपी-2020) के कार्यान्वयन के लिए मसौदा मानदंड, दिशा-निर्देश और प्रक्रियायें सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रकाशित की जाती है। ■